



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 301]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 1984/आषाढ़ 7, 1906

No. 301]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 1984/ASADHA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 28 जून, 1984

कां०आ० 472(अ)/18कक/आई डी आर ए/84:—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० 320(अ)/18कक/आई डी आर ए/79, तारीख 26 मई, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) भैरव अर्पोलॉ जिप्सर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खण्ड (अ) के अधीन 25 मई, 1982 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तीन वर्ष की अवधि के विधे ग्रहण किया गया था और सचिव, वंद और वण उद्योग विकास विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार को, जिसे अब सचिव, औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार कहा जाता है, उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया गया था;

और, केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे, 30 जून, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के विधे ऐसे जारी रहने के लिये, समय-समय पर, निदेश जारी किये थे [देखिए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० कां०आ० 246(अ)/18कक/आई डी आर ए/82, तारीख 25 मई, 1982, कां०आ० 832 (अ)/18कक/आई डी आर ए/82, तारीख 24 नवम्बर, 1982, कां०आ० 365(अ)/18कक/आई डी आर ए/83, तारीख 31 मई, 1983 और कां०आ० 872(अ)/18कक/आई डी आर ए/83, तारीख 30 नवम्बर, 1983];

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 दिसम्बर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के विधे प्रभावी बना रहे:

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18कक

की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेदन देती है कि उक्त आदेश 31 दिसम्बर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिये प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० 2/23/80-सी यू एस]

ए० पी० सरवान, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

#### ORDER

New Delhi, the 28th June, 1984.

S.O. 472(E)|18AA|IDRA|84.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 320(E)|18AA|IDRA|79, dated the 26th May, 1979, (hereinafter referred to, as the said Order), the management of the whole of the Industrial Undertaking known as Messrs Apollo Zipper Company Private Limited, Calcutta, was taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of three years upto and inclusive of the 25th May, 1982 and the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal,

now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal, was authorised to take over the management of the said Industrial Undertaking;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1984 vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 246 (E)|18AA|IDRA|82, dated the 25th May, 1982, S. O. 832 (E)|18AA|IDRA|82 dated the 24th November, 1982, S. O. 385 (E)|18AA|IDRA|83, dated the 31st May, 1983 and S.O. 872(E)|18AA|IDRA|83, dated the 30th November, 1983];

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with the proviso to sub-section (2), of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1984.

[File No. 2(23)/80-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.